आज बजट में दिखेगी लोक कल्याण की छाप

9 लाख करोड़ से अधिक का होगा UP का बजट

■ NBT रिपोर्ट, लखनऊ

योगी सरकार अपने दूसरे कार्यकाल का अंतिम बजट बुधवार को पेश करेगी। प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में सरकार इस बजट को लोकलुभावन बनाने की तैयारी में है। साल 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 'लोक कल्याण संकल्प पत्र' के जरिए 130 प्रमुख वादे किए थे। सरकार अलग-अलग बजट में ज्यादातर योजनाओं के लिए रकम आवंटित कर चुकी है। अब चुनावी बजट में बचे वादे पूरा करने पर फोकस होगा।

करीब ₹9 लाख करोड़ के बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए करीब ₹2.5 लाख करोड़ आवंटित हो सकते हैं। वृद्धावस्था, निराश्रित महिला व दिव्यांग पेंशन ₹1,000 से बढ़ाकर ₹1,500 प्रति माह करने की घोषणा हो सकती है। साथ ही 1,43,450 शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाने का ऐलान हो सकता है। सरकार मेधावी छात्राओं को स्कूटी देने के संकल्प पर भी आगे बढ़ सकती है। पिछले बजट में भी इसकी घोषणा हुई थी, लेकिन योजना जमीन पर नहीं उतर पाई थी। ▶▶पेज 2

AI Image

निवेश बढ़ाने पर होगा फोकस

सरकार का फोकस औद्योगिक निवेश बढ़ाने पर भी होगा। इसके लिए इंडस्ट्रीज को दी जाने वाली सुविधाओं का लाभ पहुंचाने के लिए धनराशि आवंटन बढ़ाया जाएगा। नए इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का ऐलान भी हो सकता है।

पूर्वांचल-बुंदेलखंड पर नजर

पूर्वांचल की विशेष योजनाओं के लिए करीब ₹1,500 करोड़ और बुंदेलखंड के लिए ₹500 करोड़ दिए जा सकते है। वहीं, डिफेंस कॉरिडोर में जमीन खरीद की रफ्तार बढ़ाने के लिए भी धनराशि आवंटित की जा सकती है।

नई टाउनशिप की तैयारी

मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना के तहत नई टाउनशिप के लिए ₹3,500 करोड़ मिल सकते है। विकास प्राधिकरणों व नगर क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं के लिए ₹2,500 करोड़ और लखनऊ मेट्रो के लिए ₹500 करोड़ मिल सकते है।